

प्रेषक,

जे०पी० जोशी

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2015

**विषय:** सरस्वती बाल विद्या मन्दिर अमकोटी को ग्राम गोर्ती, तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग में विद्यालय में भवन के निर्माण हेतु कुल 0.128 है० भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-519/सात-21(2009-10), दिनांक 18.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सरस्वती बाल विद्या मन्दिर, अमकोटी को ग्राम गोर्ती, तहसील जखोली, जिला-रूद्रप्रयाग में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (विद्यालय भवन के निर्माण हेतु) कुल 0.128 है० भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विद्यालय भवन के निर्माण हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।
- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6- समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।



- 7- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 8- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 9- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 10- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 11- प्रश्नगत प्रयोजन की पूर्ति के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सम्बन्धित मानकों/शासनादेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के मानचित्र की स्वीकृति विधिवत् सम्बन्धित प्राधिकरण से करायी जानी आवश्यक होगी।
- 13- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश के अनुपालन स्थिति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव।

पू०सं०-7024 / XVIII(II) / 2015-1(66) / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 5- प्रबन्धक, सरस्वती बाल विद्या मन्दिर अमकोटी, ग्राम गोर्ती, तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग।
- 6- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(आलोक कुमार सिंह)  
अनुसचिव।